



Daily करेंट अफेयर्स

➤ 23 अगस्त 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. UIDAI और स्टारलिनक ने डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए आधार-आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए सहयोग किया।



इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत काम करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार-आधारित ग्राहक सत्यापन को सक्षम करने के लिए स्पेसएक्स के उपग्रह इंटरनेट प्रदाता, स्टारलिनक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है।

- इस सहयोग से डिजिटल प्रमाणीकरण बुनियादी ढांचे में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय हो जाएगी।

- साझेदारी स्टारलिनक को उप-प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी (SUA) और उप-इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (e-KYC) उपयोगकर्ता एजेंसी के रूप में नामित करती है, जिससे कंपनी को ग्राहक ऑनबोर्डिंग के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण करने की अनुमति मिलती है।

- इस पहल को UIDAI के CEO भुवनेश कुमार, UIDAI के उप महानिदेशक (डिप्टी-DG) मनीष भारद्वाज और स्टारलिनक इंडिया के निदेशक पर्निल उध्वरिश की उपस्थिति में औपचारिक रूप दिया गया।

Key Points:-

(i) इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य स्टारलिनक को भारत के नियामक ढांचे का अनुपालन करने में सहायता प्रदान करना है, साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरों, संस्थानों और व्यवसायों में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करना है। यह सुनिश्चित करता है कि आधार प्रमाणीकरण सुरक्षित डिजिटल पहचान सत्यापन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक बने।

(ii) आधार-आधारित प्रमाणीकरण को सक्षम करके, स्टारलिनक उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए एक निर्बाध और सुरक्षित सत्यापन प्रणाली प्रदान कर सकता है। यह कदम भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की मापनीयता और विश्वसनीयता को दर्शाता है, जो सरकार के डिजिटल इंडिया विज़न के अनुरूप है।

(iii) UIDAI ने स्पष्ट किया है कि ग्राहक ऑनबोर्डिंग के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण मौजूदा मानदंडों के अनुरूप स्वैच्छिक रहेगा। उपयोगकर्ताओं को इसमें शामिल होने या इससे बाहर होने की स्वतंत्रता होगी, जिससे भारत के डेटा गोपनीयता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होगा और साथ ही भारतीय बाजार में स्टारलिनक की उपस्थिति मजबूत होगी।

2. EPFO ने 1 अप्रैल, 2025 से अनुग्रह मृत्यु राहत निधि को बढ़ाकर ₹15 लाख कर दिया है।



अगस्त 2025 में, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए अपने मृत्यु राहत कोष (DRF) के तहत अनुग्रह लाभ को 8.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की घोषणा की, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

● इस वृद्धि का अर्थ है कि मृतक EPFO केंद्रीय बोर्ड कर्मचारी के परिवार के सदस्यों - या तो नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी - को कर्मचारी कल्याण निधि से 15 लाख रुपये मिलेंगे, जो पहले 8.80 लाख रुपये था, जिससे नुकसान के समय मजबूत वित्तीय सहायता मिलेगी।

● यद्यपि इसकी घोषणा अगस्त 2025 में की गई थी, परंतु नई अनुग्रह राशि 1 अप्रैल 2025 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उसके बाद होने वाली पात्र मौतों बिना किसी देरी के उच्च मुआवजा स्लैब के अंतर्गत आ जाएंगी।

Key Points:-

(i) यह बढ़ोतरी मृत्यु सहायता व्यवस्था में सुधार के लिए EPFO की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वकालत समूहों और EPFO अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि बढ़ी हुई सहायता राशि, जो पहले की तुलना में लगभग दोगुनी है, का उद्देश्य बढ़ती जीवन-यापन लागत और शोक संतप्त परिवारों पर पड़ने वाले भावनात्मक प्रभाव को संतुलित करना है।

(ii) इस संशोधन से पहले, अनुग्रह राशि को 1 अप्रैल, 2024 से बढ़ाकर ₹8.80 लाख कर दिया गया था। यह कदम पहले की गई वृद्धि के बाद आया है - 2021 में ₹4.20 लाख से ₹8 लाख तक - जो पिछले कुछ वर्षों में समर्थन में एक प्रगतिशील ऊपर की ओर प्रवृत्ति को दर्शाता है।

(iii) अनुग्रह राशि के वितरण में वृद्धि, EPFO द्वारा अपने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। हाल के वर्षों में शुरू की गई डिजिटल रूप से सुव्यवस्थित दावा प्रक्रियाओं के माध्यम से, बढ़ी हुई राहत प्रदान करके, EPFO का उद्देश्य शोक के दौरान त्वरित और सहानुभूतिपूर्ण सहायता सुनिश्चित करना है।

3. IEPFA ने हैदराबाद, तेलंगाना में 3 निवेशक सेवा केंद्र खोले।



अगस्त 2025 में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MoCA) के तहत कार्यरत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) ने निवेशकों को तेज और निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए हैदराबाद, तेलंगाना में तीन निवेशक सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया।

● तीन निवेशक सेवा केन्द्रों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CDSL), नेशनल

सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) के सहयोग से लॉन्च किया गया।

• इस बहु-एजेंसी प्रयास का उद्देश्य निवेशक शिकायत निवारण में सुधार करना और लंबित सेवा अनुरोधों को सुव्यवस्थित करना है।

Key Points:-

(i) नव-उद्घाटित केंद्र केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, BSE हैदराबाद कार्यालय और NSE ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद में स्थित हैं। ये केंद्र सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक कार्यरत हैं और महत्वपूर्ण वित्तीय सेवा मुद्दों के समाधान हेतु निवेशकों के साथ सीधे संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

(ii) ये केंद्र 6 से 7 वर्षों से लंबित अवैतनिक लाभांश हस्तांतरण की सुविधा, निर्बाध KYC और नामांकन अद्यतन, और निवेशक सेवा अनुरोध (ISR) फॉर्म जमा करने जैसी प्रमुख सेवाएँ प्रदान करते हैं। KYC और ISR औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद, निवेशक अपने लंबित लाभांश सीधे प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) इस पहल से देरी कम होने, सुगमता बढ़ने और बिना किसी अनावश्यक बाधा के वित्तीय अधिकार सुनिश्चित होने से हजारों निवेशकों को लाभ होने की उम्मीद है। यह पहल निवेशक सुरक्षा को मज़बूत करने और पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में IEPFA द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

4. फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के लिए 24-26 अगस्त, 2025 तक भारत का दौरा करेंगे।



फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका 24 से 26 अगस्त, 2025 तक भारत की चार दिवसीय महत्वपूर्ण आधिकारिक यात्रा पर आएँगे। यह उनकी वर्तमान पद पर पहली भारत यात्रा होगी। अपनी पत्नी सुलुएती राबुका और वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ, यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने पर ज़ोर देगी।

• अपने प्रवास के दौरान, प्रधानमंत्री राबुका नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इन उच्च-स्तरीय चर्चाओं का उद्देश्य व्यापार, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, फिजी और भारत के बीच दीर्घकालिक संबंधों को और मज़बूत करना है।

• उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने अगस्त 2024 में फिजी का दौरा किया था, जो किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र की पहली यात्रा थी।

• इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू फिजी के नासेसे में भारत के नए चांसरी और सांस्कृतिक केंद्र के लिए लीज़ प्रक्रिया को औपचारिक मान्यता देना है। इस घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच राजनयिक जुड़ाव और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ने की उम्मीद है।

Key Points:-

(i) प्रधानमंत्री राबुका नई दिल्ली में भारतीय विश्व मामलों की परिषद (ICWA) में 'शांति का महासागर' विषय पर एक भाषण भी देंगे। इस संबोधन का उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए फिजी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है।

(ii) इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो और फिजी के राष्ट्रीय व्यापार मापन एवं मानक विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग और मानकीकरण प्रथाओं को बढ़ाना है।

(iii) यह यात्रा सुवा में आयोजित छठे विदेश कार्यालय परामर्श के बाद हो रही है, जहाँ दोनों सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सहयोग के वर्तमान क्षेत्रों की समीक्षा की और गहन सहयोग के नए अवसरों की खोज की। यह यात्रा मई 2025 में प्रधान मंत्री राबुका और भारत की विदेश राज्य मंत्री, पबित्रा मार्गेरिता के बीच हुई बैठक सहित पूर्व के कार्यक्रमों पर भी आधारित है।

5. SASCI योजना 3,295.76 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ कम ज्ञात स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा देगी।



पूँजी निवेश के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत, पर्यटन

मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 23 राज्यों में 40 परियोजनाओं के लिए 3,295.76 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं - जिसका उद्देश्य कम ज्ञात लेकिन प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना है।

● SASCI योजना राज्य सरकारों को प्रतिष्ठित पर्यटन केन्द्रों के विकास, ब्रांडिंग और वैश्विक स्तर के बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए 50 वर्ष से अधिक अवधि के लिए ब्याज मुक्त पूंजी सहायता प्रदान करती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलता है और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।

● परियोजनाओं का चयन प्रतिस्पर्धी "चुनौती मोड" मूल्यांकन के माध्यम से किया गया, जिसमें कनेक्टिविटी, स्थिरता, पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र, वहन क्षमता, परिचालन प्रबंधन, विपणन क्षमता और दीर्घकालिक मूल्य को प्राथमिकता दी गई। कार्यान्वयन राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है और मंत्रालय द्वारा निरंतर प्रगति समीक्षा की जाती है।

Key Points:-

(i) इस योजना में 23 राज्यों में 40 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें गंडिकोटा किला (आंध्र प्रदेश), अरुणाचल प्रदेश में इको-रिट्रीट, असम चिड़ियाघर का पुनरुद्धार, असम में हेरिटेज केंद्र, केरल बैकवाटर और पानी के नीचे पर्यटन पहल जैसे विविध गंतव्य शामिल हैं - जो समग्र क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करते हैं।

(ii) SASCI के तहत, गुजरात को दो प्रमुख पहलों के लिए धन प्राप्त हुआ: धोर्डों में कन्वेंशन सेंटर के साथ एक टेंट सिटी (51.56 करोड़ रुपये) और केरल (मोकरसागर), पोरबंदर में एक इकोटूरिज्म गंतव्य (99.50 करोड़ रुपये), पर्यावरण के प्रति संवेदनशील डिजाइनों के साथ बुनियादी ढांचे को बढ़ाना।

(iii) कम ज्ञात स्थलों को विकसित करके, SASCI योजना का उद्देश्य पर्यटकों की आवाजाही में विविधता

लाना, रोजगार सृजन करना, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना और प्रौद्योगिकी-आधारित टिकाऊ बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है - जो भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों से आगे बढ़ना है।

INTERNATIONAL

1. भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता शुरू करने के लिए संदर्भ की शर्तों (ToR) पर हस्ताक्षर किए।



अगस्त 2025 में, भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU), जिसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य और रूस शामिल हैं, ने मॉस्को, रूस में एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों (ToR) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से व्यापार संबंधों में वृद्धि, भारतीय उत्पादों के लिए बाज़ार पहुँच में विविधता और भारत-EAEU आर्थिक संबंधों को मज़बूती मिलने की उम्मीद है।

• इस अनुबंध पर भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MoC&I) के अंतर्गत वाणिज्य विभाग (DoC) के अपर सचिव अजय भादू और यूरेशियन आर्थिक आयोग (EEC) के व्यापार नीति विभाग के उप निदेशक मिखाइल चेरकेव ने हस्ताक्षर किए।

यह भारत और EAEU के बीच वरिष्ठ नौकरशाही और नीतिगत स्तरों पर सहयोग को दर्शाता है।

• प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का उद्देश्य भारत के निर्यात को बढ़ावा देना, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को समर्थन प्रदान करना, और साथ ही EAEU क्षेत्र में भारतीय उत्पादों के लिए बाज़ार पहुँच में विविधता लाना है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मज़बूत करना और एक स्थायी व्यापारिक ढाँचा तैयार करना भी है।

• यह समझौता मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ताओं के लिए औपचारिक रूपरेखा तैयार करता है। इससे अप्रयुक्त व्यापार क्षमता के विकास, निवेश प्रवाह में सुधार और भारत-EAEU आर्थिक साझेदारी को और मज़बूत व टिकाऊ बनाने की उम्मीद है। यह समझौता भविष्य के रणनीतिक आर्थिक सहयोग और एकीकरण के लिए भी मंच तैयार करता है।

Key Points:-

(i) भारत-EAEU व्यापार कारोबार 2024 में 69 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो 2023 की तुलना में 7% की वृद्धि दर्शाता है। प्रस्तावित FTA को EAEU के 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद का समर्थन प्राप्त है, जो भारत के लिए पर्याप्त बाज़ार अवसरों का संकेत देता है। यह व्यापार संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) सहित अन्य प्रमुख भागीदारों के साथ भारत की चल रही वार्ताओं का पूरक है।

(ii) EAEU उत्तरी यूरेशिया में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ है जो वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी और श्रम के मुक्त आवागमन को सुगम बनाता है। इसकी स्थापना EAEU संधि के माध्यम से हुई थी और यह 1 जनवरी, 2015 को यूरेशियन आर्थिक समुदाय (EvrAsEs) के बाद लागू हुआ। वर्तमान में बेलारूस EAEU की अध्यक्षता कर रहा है।

(iii) EAEU के मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाना और जीवन स्तर में सुधार के लिए स्थिर विकास को बढ़ावा देना है। संघ में पाँच सदस्य देश शामिल हैं: रूस, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते से व्यापार को मज़बूती मिलने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को समर्थन मिलने और पूरे क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है।

BANKING & FINANCE

1. थॉमस कुक इंडिया ने मोबाइल के माध्यम से संपर्क रहित सीमा-पार भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई।



थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड अपने प्रीपेड विदेशी मुद्रा (forex) कार्ड को गूगल पे के साथ एकीकृत करके संपर्क रहित सीमा पार भुगतान को सक्षम करने वाला पहला भारतीय विदेशी मुद्रा-सेवा प्रदाता बन गया है, जो वीज़ा के सुरक्षित टोकनाइजेशन द्वारा संचालित है, जो उपयोगकर्ताओं को 95 से अधिक देशों में सहज टैप-एंड-पे और ऑनलाइन भुगतान प्रदान करता है।

● एक अग्रणी कदम के तहत, थॉमस कुक इंडिया ने गूगल पे और वीज़ा के साथ साझेदारी की है ताकि बॉर्डरलेस ट्रेवल, वन करेंसी, स्टडी बडी और

एंटरप्राइजएफएक्स जैसे अपने प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड के उपयोगकर्ता अपने मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके विदेश में संपर्क रहित भुगतान कर सकें। इस पहल के साथ, थॉमस कुक इंडिया मोबाइल-आधारित क्रॉस-बॉर्डर टैप-एंड-पे सुविधा प्रदान करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है।

● कार्डधारक 95 देशों तक के भौतिक पॉइंट-ऑफ़-सेल आउटलेट्स या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर लेनदेन आसानी से कर सकते हैं। गूगल पे के साथ एकीकरण उन्नत नेटवर्क टोकनाइजेशन मानकों के माध्यम से बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है, कार्ड खोने या धोखाधड़ी जैसे जोखिमों को कम करता है, साथ ही तेज़ और सुविधाजनक भुगतान अनुभव प्रदान करता है।

● यह पहल भारत के यात्रा और भुगतान परिदृश्य में उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं के अनुरूप है—खासकर मिलेनियल्स और जेन-ज़ेड के बीच। यूपीआई के आँकड़े डिजिटल अपनाने में एक बड़ी छलांग को दर्शाते हैं: अकेले अक्टूबर 2024 में, इसने ₹23.49 लाख करोड़ मूल्य के 16.58 अरब लेनदेन संसाधित किए, जो साल-दर-साल 45% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, थॉमस कुक की रिपोर्ट के अनुसार, अब उसका 20% से ज़्यादा विदेशी मुद्रा कारोबार उसके पोर्टल, ऐप और व्हाट्सएप सेवाओं जैसे डिजिटल माध्यमों से आता है।

Key Points:-

(i) थॉमस कुक (भारत) में विदेशी मुद्रा विनिमय के कार्यकारी उपाध्यक्ष दीपेश वर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल सुरक्षा, गति और सुविधा को मिलाकर "वैश्विक भारतीयों" की अपेक्षाओं को पूरा करती है।

(ii) वीज़ा इंडिया के कंट्री मैनेजर ऋषि छाबड़ा ने इस सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यह आज के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए उपयुक्त "अत्याधुनिक

डिजिटल भुगतान समाधान" प्रदान करता है, साथ ही लेनदेन की सहजता और सुरक्षा को बढ़ाता है।

(iii) मोबाइल-प्रथम डिज़ाइन, टोकनयुक्त सुरक्षा और सीमा-रहित उपयोगिता के सम्मिश्रण द्वारा, थॉमस कुक इंडिया का नवाचार यात्रा भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्परिभाषित करने के लिए तैयार है। यह सीमा-पार विदेशी मुद्रा लेनदेन में उपभोक्ता अपेक्षाओं और सेवा मानकों को नया आकार देने के लिए तैयार है, और Google Pay और वीज़ा के साथ साझेदारी का लाभ उठाकर, सहज, सुरक्षित और विश्वव्यापी रूप से स्वीकृत मोबाइल भुगतान समाधान प्रदान करके, "भारत का विदेशी मुद्रा विशेषज्ञ" के रूप में थॉमस कुक की स्थिति को और मज़बूत करेगा।

2. AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का उपयोग करने वाले NRE/NRO खाताधारकों के लिए UPI शुरू किया।



एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU SFB) ने एक अग्रणी पहल शुरू की है, जिसके तहत अनिवासी बाह्य (NRE) और अनिवासी साधारण (NRO) खाताधारकों को चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के मोबाइल नंबरों का उपयोग करके UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है - जिससे भारतीय सिम की आवश्यकता समाप्त हो गई है

और भारत में निर्बाध डिजिटल लेनदेन सरल हो गया है।

● AU SFB अब NRE और NRO खाताधारकों को UPI एक्सेस के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, हांगकांग, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब और सिंगापुर सहित 12 देशों में अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर पंजीकृत करने की अनुमति देता है। यह सुविधा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के एक निर्देश के बाद शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के लिए UPI की पहुँच को व्यापक बनाना है।

● इस अपडेट के साथ, NRIs UPI का इस्तेमाल कई तरह के लेन-देन के लिए कर सकते हैं—चाहे वह पीयर-टू-पीयर ट्रांसफर हो, बिल भुगतान हो, या मर्चेन्ट क्यूआर कोड-आधारित खरीदारी हो—बिना किसी भारतीय मोबाइल कनेक्शन की ज़रूरत के। यह सेवा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध है, जिससे विदेश से दक्षता, सुरक्षा और वित्तीय सुविधा में वृद्धि होती है।

Key Points:-

(i) AU SFB के कार्यकारी निदेशक और उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तम टिबरेवाल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह पहल भारत के डिजिटल इंडिया मिशन का समर्थन करते हुए और अभिनव, समावेशी डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देते हुए प्रवासी भारतीयों के लिए "पारंपरिक बाधाओं को तोड़ती है"। यह कदम वैश्विक भारतीयों को भारत के डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकृत करने की AU SFB की प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है।

(ii) यह विकास एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है: कई भारतीय बैंक और UPI ऐप अब NPCI और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अद्यतन ढाँचों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का समर्थन करते हैं। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC और अन्य जैसे प्रमुख बैंक इस विस्तार का हिस्सा हैं।

(iii) इससे पहले, UPI की पहुंच भारतीय मोबाइल नंबरों तक सीमित थी; अब, NRE/NRO खाताधारक अपने स्थानीय मोबाइल कनेक्शन का उपयोग करके UPI की सुविधा का आनंद ले सकते हैं।

ECONOMY & BUSINESS

1. SBI रिसर्च इकोरैप ने भारत की Q1 FY26 GDP वृद्धि दर 6.8%-7.0% रहने का अनुमान लगाया है, जो RBI के अनुमान से अधिक है।



अगस्त 2025 में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के आर्थिक अनुसंधान प्रभाग, SBI रिसर्च ने अपनी इकोरैप रिपोर्ट जारी की, जिसमें वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 6.8%-7.0% रहने का अनुमान लगाया गया, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 6.5% के अनुमान से अधिक है।

- SBI रिसर्च के इकोरैप ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान जताया है, जो कमजोर निजी निवेश गति के बावजूद सरकारी पूंजीगत व्यय और लचीली खपत से प्रेरित है।

- रिपोर्ट में वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के लिए सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो व्यापक-आधारित क्षेत्रीय योगदान को दर्शाता है, लेकिन औद्योगिक

और कृषि प्रदर्शन में असमान सुधार पैटर्न को रेखांकित करता है।

- पूरे वित्त वर्ष 26 के लिए, SBI रिसर्च ने भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है, जो RBI के 6.5% के अनुमान से थोड़ा कम है, जो आगामी तिमाहियों में गति की स्थिरता के बारे में चिंताओं को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) SBI रिसर्च ने वित्त वर्ष 26 की शेष तिमाहियों के लिए भारत के GDP परिदृश्य को संशोधित किया है, प्रत्येक तिमाही में 20 आधार अंकों की कटौती की है। इसने दूसरी तिमाही में 6.5%, तीसरी तिमाही में 6.3% और चौथी तिमाही में 6.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो सतर्क आर्थिक गति को दर्शाता है।

(ii) SBI रिसर्च ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की ओर से पूंजीगत व्यय (Capex) विकास को गति प्रदान कर रहा है, जबकि निजी क्षेत्र का निवेश धीमा बना हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूत विकास गति प्राप्त करने में बाधा आ रही है।

(iii) इकोरैप रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि उपभोग में लचीलापन बना हुआ है, लेकिन मुद्रास्फीति के दबाव, राजकोषीय अनुशासन और बाह्य व्यापार चुनौतियों को संतुलित करना भारत के लिए अपने मध्यम अवधि के विकास के दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

2. भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 तक राजमार्ग परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से ₹1.42 लाख करोड़ जुटाए।



वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक, भारत सरकार ने राजमार्ग परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके लगभग ₹1.42 लाख करोड़ जुटाए हैं - जो इसकी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) का एक प्रमुख आकर्षण है - और चालू वित्त वर्ष में अनुमानित ₹30,000 करोड़ की उम्मीद है।

- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार ने विभिन्न तंत्रों के माध्यम से वित्त वर्ष 2025 तक राजमार्ग परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से 1,42,758 करोड़ रुपये जुटाने की सूचना दी है।

- तीन मुद्रीकरण मार्गों के माध्यम से धन जुटाया गया: टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (ToT), इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT), और विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs) के माध्यम से प्रतिभूतिकरण।

Key Points:-

(i) सरकार को चालू वित्त वर्ष में इसी राजमार्ग मुद्रीकरण ढांचे के माध्यम से अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है, जिससे बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में गति बनी रहेगी।

(ii) यह उपलब्धि चार वर्षीय NMP की पृष्ठभूमि में सामने आई है, जिसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2025 के बीच केंद्र सरकार की परिसंपत्तियों से 6 लाख करोड़ रुपये मूल्य का मूल्य प्राप्त करना

है।

(iii) इस सफलता के आधार पर, केंद्रीय बजट 2025 में दूसरी परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना पेश की गई, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 26 से वित्त वर्ष 30 तक 10 लाख करोड़ रुपये जुटाना है, जिसका उद्देश्य नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में आय का पुनर्निवेश करना है।

3. CCPA ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।



केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर "गारंटीड ऑटो" और "5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये प्राप्त करें" जैसे भ्रामक विज्ञापनों के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिससे ग्राहकों को तुरंत रिफंड और अनुपालन अनिवार्य हो गया है।

- CCPA ने रैपिडो के दावों - "गारंटीड ऑटो" और "5 मिनट में ऑटो या ₹50 प्राप्त करें" - की स्वतः संज्ञान जांच शुरू की और निष्कर्ष निकाला कि इन प्रचारों ने गारंटीकृत सेवाओं और लाभों का अति-वादा करके उपभोक्ताओं को गुमराह किया।

- आगे की जांच से पता चला कि वादा किया गया ₹50 वास्तविक नकदी नहीं था, बल्कि "रैपिडो सिक्के" थे, जो केवल बाइक की सवारी के लिए

मान्य थे, सात दिनों में समाप्त हो रहे थे, और अज्ञात शर्तों के अधीन थे - जिससे वादे का वास्तविक मूल्य कम हो गया।

Key Points:-

(i) जून 2024 और जुलाई 2025 के बीच राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की संख्या बढ़कर 1,224 हो गई, जो पिछली अवधि में 575 थी। CCPA ने रैपिडो को प्रभावित उपयोगकर्ताओं को धन वापस करने, भ्रामक विज्ञापनों को हटाने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(ii) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और 2022 के विज्ञापन दिशानिर्देशों के तहत कार्य करते हुए, CCPA ने उपभोक्ता पारदर्शिता को बनाए रखने और भ्रामक वाणिज्यिक प्रथाओं को रोकने के लिए दंड लागू किया, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसके नियामक रुख को मजबूती मिली।

MOUs and Agreement

1. DEPwD, निपमैन फाउंडेशन और YLAC ने 'ब्रेकिंग बैरियर्स फेलोशिप' शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

DEPwD, Nipman Foundation & YLAC Ink MoU to Launch 'Breaking Barriers Fellowship'



अगस्त 2025 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) ने निपमैन फाउंडेशन और यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटीजनशिप (YLAC) के साथ

संयुक्त रूप से "ब्रेकिंग बैरियर्स फेलोशिप" शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए नवाचार, वकालत और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया एक कार्यक्रम है।

• "ब्रेकिंग बैरियर्स फेलोशिप" दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, निपमैन फाउंडेशन और YLAC के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। निपमैन फाउंडेशन सुलभता और समावेशी प्रथाओं में अपनी मज़बूत वकालत करता है, जबकि YLAC युवा नेतृत्व को सशक्त बनाने में अपनी विशेषज्ञता का योगदान देता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दिव्यांगजन अधिकारों को उनके साथियों के नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से बढ़ावा देना है।

• इस समझौते के तहत, फेलोशिप हैकाथॉन, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं और समावेशी समान अवसर पुरस्कारों जैसी पहलों के माध्यम से विकलांगता अधिकारों के बारे में जागरूकता और नवाचार को बढ़ावा देगी। इन आयोजनों का उद्देश्य प्रणालीगत परिवर्तन को प्रेरित करना और सुगम्यता में सर्वोत्तम प्रथाओं को मान्यता प्रदान करना है।

• यह समझौता व्यापक समावेशन प्रयासों से उपजा है, जिसे समावेशी भारत शिखर सम्मेलन के दौरान रेखांकित किया गया था - जिसका आयोजन वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस पर किया गया था - जहां दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने भारत के सुगम्यता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए निपमैन फाउंडेशन और वाईएलएसी सहित अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ साझेदारी को औपचारिक रूप दिया था।

Key Points:-

(i) निपमैन फाउंडेशन सुलभता ऑडिट, जागरूकता अभियानों (समान अवसर पुरस्कारों सहित) और विकलांग व्यक्तियों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए "व्हील्स फॉर लाइफ़" जैसी ज़मीनी पहलों के लिए

जाना जाता है। YLAC नागरिक नेतृत्व कार्यक्रमों और सार्वजनिक नीति वकालत के माध्यम से युवाओं को जोड़ने में मज़बूती लाता है।

(ii) यह फ़ेलोशिप समावेशी कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) की दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। युवाओं की सहभागिता और सामुदायिक नवाचार का लाभ उठाकर, यह समावेशी सामाजिक परिवर्तन को गति प्रदान करता है और एक सुलभ एवं समतामूलक समाज के निर्माण के DEPwD के मिशन का समर्थन करता है।

2. BVFCL ने भूटान के राष्ट्रीय बीज केंद्र के साथ 5-वर्षीय उर्वरक आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए।



अगस्त 2025 में, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (MoCF) के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU), ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड (BVFCL) ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित भूटान के राष्ट्रीय बीज केंद्र (NSC) के साथ 5-वर्षीय बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता कृषि में भारत-भूटान सहयोग को मज़बूत करता है और सीमा पार उर्वरक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

• रसायन और उर्वरक मंत्रालय (MoCF) के तहत संचालित ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड (BVFCL) समझौते के हिस्से के रूप में भूटान को आवश्यक उर्वरकों की आपूर्ति करेगा।

• उत्पादों में यूरिया, सुफला (NPK), सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP), म्यूरेट ऑफ पोटाश (MoP) और बोरेक्स शामिल हैं, जो मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

• इस समझौते का उद्देश्य भूटान के लिए महत्वपूर्ण उर्वरकों की निर्बाध और समय पर पहुँच सुनिश्चित करना है। इससे भूटान की कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा लक्ष्यों को प्रत्यक्ष रूप से बल मिलेगा, और यह सुनिश्चित होगा कि इस हिमालयी राष्ट्र के किसानों को प्रमुख कृषि आदानों की विश्वसनीय आपूर्ति मिलती रहे।

Key Points:-

(i) यह पाँच वर्षीय व्यापार-से-व्यापार समझौता भारत की क्षेत्रीय कृषि सहयोग की व्यापक रणनीति को दर्शाता है। उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करके, यह समझौता टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देता है, भूटान की इनपुट आपूर्ति चुनौतियों का समाधान करता है, और फसल चक्रों के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने में सहायता करता है।

(ii) पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में समझौते पर हस्ताक्षर सीमा पार व्यापार और रसद के लिए रणनीतिक स्थान को उजागर करते हैं। यह कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से भूटान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

(iii) यह रणनीतिक साझेदारी भारत-भूटान संबंधों, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में, एक मील का पत्थर है। यह न केवल उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करती है, बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच पारस्परिक विकास, क्षेत्रीय स्थिरता और खाद्य सुरक्षा में सहयोग को भी

बढ़ावा देती है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. मुख्यमंत्री पर हमले के बाद राजधानी की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया।



एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है - तत्काल प्रभाव से - सुरक्षा उल्लंघन के बाद उजागर हुई कमजोरियों के बाद, जिसका उद्देश्य जनता का विश्वास बहाल करना और राजधानी में कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाना है।

● दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर हुई सुरक्षा चूक के बाद गृह मंत्रालय (MHA) ने तुरंत कार्रवाई की, जहाँ एक जनसुनवाई के दौरान उन पर हमला हुआ। घटना के 24 घंटे के भीतर ही, गृह मंत्रालय ने कार्यवाहक पुलिस आयुक्त को हटाकर सतीश गोलचा को इस पद पर नियुक्त कर दिया।

● गोलचा 1992 बैच के AGMUT कैडर के एक अनुभवी IPS अधिकारी हैं, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं: महानिदेशक (कारागार), विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था, ज़ोन 2), विशेष पुलिस आयुक्त (खुफिया), पुलिस उपायुक्त

(DSP), और संयुक्त पुलिस आयुक्त। उल्लेखनीय है कि उन्होंने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कानून-व्यवस्था को संभाला था—संकट की स्थितियों में उनकी सिद्ध विशेषज्ञता को उनके नए कार्यभार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

● सतीश गोलचा 1988 बैच के IPS अधिकारी और महानिदेशक (होमगार्ड्स) SBK सिंह का स्थान लेंगे, जो संजय अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद 1 अगस्त से कार्यवाहक दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। मुख्यमंत्री के हमले के बाद कड़ी निगरानी के बीच सिंह का अंतरिम कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया।

Key Points:-

(i) गृह मंत्रालय की औपचारिक अधिसूचना में कहा गया है: "सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, सतीश गोलचा, जो वर्तमान में दिल्ली के महानिदेशक (कारागार) के पद पर तैनात हैं, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक दिल्ली के पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है।" उनकी नियुक्ति को राजधानी के पुलिसिंग ढांचे में विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए एक अभिन्न अंग माना जा रहा है।

(ii) हमले के बाद, CM रेखा गुप्ता की सुरक्षा को 'जेड' श्रेणी में अपग्रेड कर दिया गया और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को सौंप दिया गया।

(iii) गृह मंत्रालय ने भी गहन जांच का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार हुआ, सार्वजनिक सुनवाई के दौरान संरचित पहुंच और सख्त परिधि नियंत्रण उपाय किए गए - ये सभी गोलचा के नेतृत्व में अधिक सतर्क दृष्टिकोण का संकेत देते हैं।

IMPORTANT DAYS

1. आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025, 21 अगस्त को मनाया गया।

INTERNATIONAL DAY OF REMEMBRANCE AND TRIBUTE TO VICTIMS OF TERRORISM

2025 21 AUGUST

संयुक्त राष्ट्र (UN) 21 अगस्त 2025 को आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएगा, जो आठवाँ वार्षिक स्मरणोत्सव होगा। यह दिन पीड़ितों को सम्मानित करता है, बचे लोगों का समर्थन करता है और मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देता है।

- 2025 के स्मरणोत्सव का विषय था "आशा से एकजुट: आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सामूहिक कार्रवाई।" इस विषय ने प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों के लिए न्याय, सम्मान और दीर्घकालिक सहायता सुनिश्चित करने में वैश्विक एकजुटता पर ज़ोर दिया।

- इस दिवस की शुरुआत जून 2011 में मानवाधिकार परिषद (HRC) के 17वें सत्र से हुई, जिसमें प्रस्ताव A/HRC/RES/17/8 के माध्यम से, प्रारंभ में 19 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रस्तावित किया गया था।

Key Points:-

(i) 19 दिसंबर 2017 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने प्रस्ताव A/RES/72/165 को अपनाया, जिसके तहत आधिकारिक तौर पर हर साल 21

अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस प्रस्ताव ने वैश्विक मान्यता और वार्षिक पालन को संस्थागत रूप दिया।

(ii) पहला आधिकारिक आयोजन 21 अगस्त 2018 को हुआ, जिससे पीड़ितों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वकालत करने और मानवाधिकारों को कायम रखते हुए आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए एक मंच तैयार हुआ।

(iii) 2025 तक यह स्मरणोत्सव एक वैश्विक आंदोलन बन चुका होगा, जिसमें 8वें स्मरणोत्सव के माध्यम से पीड़ितों के लिए सहायता प्रणालियों को आगे बढ़ाने और आतंकवादी कृत्यों को रोकने में सरकारों, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय निकायों की भूमिका को सुदृढ़ किया जाएगा।

2. मद्रास दिवस 22 अगस्त 2025 को मनाया गया।

MADRAS DAY CELEBRATED 22 AUGUST 2025

मद्रास शहर (अब चेन्नई) हर साल 22 अगस्त को मद्रास दिवस मनाता है, जो 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंटों द्वारा मद्रासपट्टनम की खरीद का प्रतीक है - जो भारत की सबसे प्रारंभिक औपनिवेशिक बस्तियों में से एक थी।

● 22 अगस्त 1639 को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकारियों फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन के माध्यम से स्थानीय नायक शासकों से मद्रासपट्टनम नामक तटीय पट्टी का अधिग्रहण किया - और इस प्रकार मद्रास शहर के विकास की नींव रखी।

● मद्रास दिवस को वार्षिक उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत 2004 में चेन्नई के इतिहासकार एस. मुथैया, विन्सेंट डिसूजा (माइलापुर टाइम्स के संपादक) और शशि नायर (निदेशक/संपादक, प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया) द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य शहर की समृद्ध विरासत का जश्न मनाना था।

Key Points:-

(i) इस स्मरणोत्सव में विरासत भ्रमण, वार्ता, प्रदर्शनियां, खाद्य महोत्सव, प्रश्नोत्तरी, फोटो प्रतियोगिताएं और बहुत कुछ शामिल है - जिससे समुदायों, स्कूलों, सांस्कृतिक समूहों और पर्यटकों को शहर के इतिहास, वास्तुकला, भोजन और बहुसांस्कृतिक विरासत की खोज करने में मदद मिलेगी।

(ii) 1639 के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण हुआ और जॉर्ज टाउन जैसी आसपास की बस्तियों का विकास हुआ, जो अंततः चेन्नई के विशाल महानगर में विस्तारित हो गया - जो अब भारत में एक प्रमुख सांस्कृतिक, शैक्षिक और आर्थिक केंद्र है।

(iii) मद्रास दिवस पिछले कुछ वर्षों में विस्तारित हुआ है - एक दिन से लेकर "मद्रास सप्ताह" या उससे भी अधिक समय तक - शहर भर में सौ से अधिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है जो नागरिक गौरव, जागरूकता, एकता और चेन्नई की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को दर्शाते हैं।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. NASA और IBM ने सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए 'सूर्य' AI मॉडल लॉन्च किया।



अगस्त 2025 में, नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स (IBM) के साथ साझेदारी में 'सूर्य' नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित हेलियोफिजिक्स फाउंडेशनल मॉडल पेश किया, जिसे सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने और भविष्यवाणी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

● सूर्य मॉडल को IBM कॉर्पोरेशन के सहयोग से NASA के डेटा विज्ञान कार्यालय की इंटरएजेंसी कार्यान्वयन और उन्नत अवधारणा टीम (IMPACT) के तहत विकसित किया गया है।

● यह उन्नत हेलियो-AI फाउंडेशन मॉडल पर आधारित है और इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उपग्रहों, पावर ग्रिड और संचार नेटवर्क को प्रभावित करने वाली सौर गतिविधियों की पूर्वानुमान सटीकता में सुधार करना है।

● इस मॉडल का नाम 'सूर्य' संस्कृत शब्द 'सूर्य' से लिया गया है। यह 2010 में लॉन्च किए गए NASA के सोलर डायनेमिक्स ऑब्ज़र्वेटरी (SDO) द्वारा एकत्रित उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा का उपयोग करता है, जिसने 15 वर्षों से भी अधिक समय से हर 12 सेकंड में विभिन्न तरंगदैर्घ्य में निर्बाध सौर चित्र प्रदान किए हैं।

यह निरंतर डेटासेट सूर्य की पूर्वानुमान क्षमताओं का आधार है।

Key Points:-

(i) SDO से नौ वर्षों के निरंतर अवलोकनों पर प्रशिक्षित, AI मॉडल अभूतपूर्व सटीकता के साथ दो घंटे पहले तक सौर गतिविधि का दृश्य पूर्वानुमान उत्पन्न कर सकता है। यह पारंपरिक पूर्वानुमान विधियों की तुलना में पूर्वानुमान दक्षता को लगभग 16% तक बढ़ा देता है।

(ii) इस मॉडल को अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (NSF) द्वारा संचालित एक पहल, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च रिसोर्स (NAIRR) पायलट द्वारा समर्थित किया गया था। यह NVIDIA जैसे उद्योग जगत के दिग्गजों के सहयोग से AI टूल्स, डेटासेट और कंप्यूटिंग एक्सेस को एकीकृत करता है, जिससे हीलियोफिजिक्स और AI अनुसंधान में व्यापक वैज्ञानिक नवाचार संभव हो पाता है।

(iii) सूर्य का प्राथमिक उद्देश्य सौर ज्वालाओं और विस्फोटों के प्रारंभिक संकेतों का पता लगाकर उपग्रहों, संचार प्रणालियों, विमानन और विद्युत ग्रिडों के लिए सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करना है। यह पूर्वानुमान क्षमता अंतरिक्ष मौसम संबंधी व्यवधानों के दौरान बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा और तकनीकी संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

2. भारत ने ITU-R IMT-2030 फ्रेमवर्क और भारत 6G विजन के आधार पर 2030 तक 6G रोडमैप की रूपरेखा तैयार की।



21 अगस्त 2025 को, भारत सरकार ने 2030 तक 6G परिनियोजन के लिए अपना रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत किया, जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की अनुशंसा ITU-R M.2160 के अनुरूप है और स्वदेशी भारत 6G विजन दस्तावेज़ द्वारा निर्देशित है।

● भारत का 6G रोडमैप ITU-R अनुशंसा M.2160 पर आधारित है, जो IMT-2030 प्रणालियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ढाँचा है। यह सुनिश्चित करता है कि देश में इसकी शुरुआत वैश्विक प्रौद्योगिकी और नियामक मानकों के अनुरूप हो।

● मार्च 2023 में जारी भारत 6G विजन, भारत के लक्ष्य को परिभाषित करता है, "6G नेटवर्क प्रौद्योगिकियों को डिजाइन, विकसित और तैनात करना जो सर्वव्यापी, बुद्धिमान और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं", जो सामर्थ्य, स्थिरता और सर्वव्यापकता पर जोर देता है।

● स्वदेशी नवाचार में तेजी लाने के लिए, भारत ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (TTDF) के तहत 104 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए 275 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है और 6जी-तैयार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है।

Key Points:-

(i) भारत ने भारत 6G गठबंधन की स्थापना की है,

जो उद्योग, शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थानों और मानक निकायों का एक बहु-हितधारक संघ है। यह 6G मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान, नीतिगत इनपुट और वैश्विक सहयोग का समन्वय करता है।

(ii) संचार मंत्री डॉ. पेम्मासांनी चंद्रशेखर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में रोडमैप की पुष्टि की, जिसमें रणनीतिक दृष्टि, पर्याप्त वित्त पोषण और संस्थागत तत्परता द्वारा समर्थित 2030 तक वैश्विक 6जी नेता के रूप में उभरने की भारत की महत्वाकांक्षा को रेखांकित किया गया।

3. ISRO दिसंबर 2025 में गगनयान की पहली मानवरहित परीक्षण उड़ान का संचालन करेगा।



21 अगस्त, 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि पहला मानवरहित गगनयान मिशन - जिसमें एक मानव अंतरिक्ष रोबोट होगा - दिसंबर 2025 में लॉन्च होगा, जो भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान आकांक्षाओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा।

- ISRO का आगामी गगनयान-1 (G1) मिशन इस कार्यक्रम की पहली मानवरहित कक्षीय उड़ान होगी। यह व्योममित्रा नामक एक अर्ध-मानव रोबोटिक अंतरिक्ष यात्री को अपने साथ ले जाएगा,

जो मानव कार्यों का अनुकरण करेगा और पर्यावरण नियंत्रण, वैमानिकी और जीवन रक्षक प्रणाली जैसी महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यान प्रणालियों की निगरानी करेगा।

- यह मिशन दिसंबर 2025 में निर्धारित है, और प्रक्षेपण कार्य सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC-SHAR) से संचालित किए जाएंगे। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में एक मिशन करेगा—जिसमें कक्षीय गतिविधियों के माध्यम से प्रणाली सत्यापन और पुनर्प्राप्ति शामिल है—और उसके बाद सुरक्षित रूप से पुनःप्रवेश करेगा।

Key Points:-

(i) ISRO ने अध्यक्ष वी. नारायणन के मार्गदर्शन में 2025 को 'गगनयान वर्ष' घोषित किया है। 7,200 से ज्यादा सिस्टम परीक्षण पूरे हो चुके हैं, जबकि लगभग 3,000 और परीक्षण लंबित हैं। सभी सिस्टम उड़ान के लिए तैयार हों, यह सुनिश्चित करने के लिए 24/7 तैयारियाँ जारी हैं।

(ii) G1 का मुख्य उद्देश्य तीन दिनों का कक्षीय प्रवास प्राप्त करना है, जिसके दौरान व्योममित्र और अन्य उपकरण जीवन रक्षक प्रणालियों, नेविगेशन, पुनः प्रवेश गतिशीलता और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, विकिरण और तापीय तनाव के तहत अंतरिक्ष यान के लचीलेपन का आकलन करेंगे। इससे चालक दल के मिशनों से पहले महत्वपूर्ण मापदंडों की पुष्टि हो सकेगी।

(iii) G1 का सफल प्रक्षेपण कम से कम तीन मानवरहित परीक्षण उड़ानों की श्रृंखला में पहला है, जो 2027 की शुरुआत में भारत की पहली मानवयुक्त गगनयान उड़ान का मार्ग प्रशस्त करता है। यह मिशन एक छोटी कक्षीय परीक्षा में एक से तीन अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा, जिससे भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान में वैश्विक नेताओं में शामिल हो जाएगा।

Static GK

Employees' Provident Fund Organisation (EPFO)	स्थापना: 1952	मुख्यालय: नई दिल्ली
Fiji	प्रधान मंत्री: सितिवनी राबुका	राजधानी: सुवा
Ministry of Home Affairs (MHA)	केंद्रीय मंत्री: अमित शाह	मुख्यालय: नई दिल्ली
Thomas Cook (India) Limited	CEO : महेश अय्यर	मुख्यालय: लोअर परेल, मुंबई
Rapido	CEO : अरविंद सांका	मुख्यालय: बैंगलोर
International Business Machines (IBM)	CEO : अरविंद कृष्णा	मुख्यालय: अरमोंक, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
ISRO	अध्यक्ष: वी. नारायणन	मुख्यालय: बेंगलुरु